हिन्दी दैनिक

आर.एन.आई.नं.:-UPHIN/2005/16132

उपभोक्ता की दुनिया

श्रावस्ती से प्रकाशित

वर्ष : 21 अंक : 20 | श्रावस्ती, गुरूवार 26 जून 2025 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : 1 रूपया

अचानक बिगड़ी उपराष्ट्रपति की तबीयत

नैनीताल (एजन्सी)। कुमाऊं विश्वविद्यालय का कार्यक्रम खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबीयत खराब हो गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बुधवार को तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी आर्मी हैलीपेड पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री की ओर से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, सांसद अजय भट्ट, हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट, वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष दीपक महरा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया था। नैनीताल में कुमाऊं विश्वाविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि थे। अपने 45 मिनट के संबोधन में उन्होंने बार–बार कार्यक्रम में उपस्थित 1989 में अपने साथ सांसद रहे डॉ. महेंद्र सिंह पाल का जिक्र किया। कार्यक्रम के बाद मंच से उतरकर उन्होंने डॉ पाल को गले लगाया।

इमरजेंसी को लेकर 2 मिनट रखा मौन

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल के दौरान पीड़ित अनगिनत व्यक्तियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने उन लोगों के सम्मान में दो मिनट का मौन भी रखा, जिनके संवैधानिक रूप से गारंटीकृत लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे और जिन्होंने एक सत्तावादी शासन के तहत अनगिनत पीड़ाएँ झेली थीं। मंत्रिमंडल ने संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि आपातकाल की भयावहता को कभी भुलाया नहीं जाएगा। यह आयोजन आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक है एक शक्तिशाली याद दिलाता है। कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करने और सम्मानित करने का संकल्प लिया है।

पालघर के स्कूल को दी गयी बम से उड़ाने की धमकी!

महाराष्ट्र (एजेन्सी)। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक निजी स्कूल को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को स्कूल परिसर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। मीरा–भायंदर वसई–विरार (एमबीवीवी) पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी अफवाह निकली क्योंकि नालासोपारा स्थित स्कूल के परिसर में जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नालासोपारा मुंबई का एक सुदूरवर्ती उपनगर है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूल को एक ईमेल मिला था जिसमें बताया गया था कि स्कूल परिसर में बम रखा है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को बाहर निकाला।

भारी बारिश से नहर में गिरी कार ,चार की मौत

उत्तराखंड (एजेन्सी)। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हल्द्वानी में भारी बारिश के बीच बुधवार को सात लोगों को ले जा रही एक कार के सड़क से उतरकर उफनती नहर में गिर जाने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक चार दिन का शिशु भी शामिल है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मृतकों में एक चार दिन का शिशु, दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तीन घायल लोगों को बचा लिया गया है और उनका अभी इलाज चल रहा है। कार सिंचाई नहर में गिरकर लगभग पलट गई। इस दौरान कार में पानी भर गया। कार में 4 लोग सवार थे। जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं।

सीएम योगी बोले- मोदी राज में किसानों में आई खुशहाली, अब किसान आत्महत्या नहीं करता है

लखनऊ (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण कृषि के क्षेत्र में जो विकास हो सकता था वो नहीं हो पाया। इससे हमारे किसान लाभ से वंचित रह गए। योजनाएं आपस में धन के बंदरबांट के लिए बनती थीं और हमारे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाता था। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश में समग्र विकास की जो अवधारणा विकसित हुई है। उससे देश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ में गोरखपुर, कानपुर एवं कन्नौज के डेयरी प्लांट्स तथा अंबेडकरनगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के मध्य एमओयू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के परिणाम स्वरूप अब किसानों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब अन्नदाता किसान खुशहाल है। आत्महत्या नहीं करता है। आज उसे कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य सेक्टरों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। तकनीक भी मिलती है और सरकार हर प्रकार से उसे सहयोग करने के लिए तत्पर भी रहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार अपने सरकारी आवास, 5.कालिदास मार्ग, लखनऊ में आयोजित एक भव्य समारोह में गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट्स, साथ ही अम्बेडकरनगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी तथा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राज्य के डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगा, जिससे किसानों का सीधा फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे जहाँ इन जिलों में डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा, वहीं राज्य का दुग्ध उत्पादन और भी सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह एमओयू प्रदेश में डेयरी से जुड़े छोटे व मध्यम किसान–उद्योजकों को सशक्त बनाएगा,।

जिससे वे आधुनिक तकनीकों और बेहतर सैनिटेशन प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल यूपी को दूध उत्पादन का देश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जैसा कि पहले भी नौ नए डेयरी प्लांट्स की स्थापना की योजना में देखा गया था। एनडीडीबी तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और कर्यकारी मानकों का निर्धारण करेगा।

यूपी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वितरण, विपणन, ट्रेडमार्क शब्दाधिकार, और किसानों को सीधा लाभ सुनिश्चित करेगी।

क्षेत्रीय असर और किसान–उद्योग के फायदे गोरखपुर, कानपुर, कन्नौज जैसे जिलों में डेयरी प्लांट्स को कब्जे पर दी जाने वाली भूमि 10 साल के पट्टे पर ली जाएगी, जिससे स्थानीय दूध संघ मजबूत होंगे। किसानों को बेहतर मूल्य मिलेंगे और डेयरी से जुड़े युवाओं को नौकरियाँ एवं स्वरोजगार के मौके मिलेंगे। पशु आहार निर्माणशाला, अम्बेडकरनगर का संचालन सुनिश्चित करने से पशुपालन की लागत कम होगी और पशु स्वास्थ्य बेहतर होगा।

अंतरिक्ष से आया शुभांशु का दिल छू लेने वाला पहला संदेश, भावुक हुए मां-बाप

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सिओम स्पेस द्वारा संचालित वाणिज्यिक मिशन के तहत बुधवार को तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया। रूसी अंतरिक्ष यान के जरिये भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के 41 साल बाद किसी भारतीय की यह यात्रा हो रही है।

41 साल पहले भारत के राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सैल्यूट–7 अंतरिक्ष स्टेशन के तहत कक्षा में आठ दिन रहे थे। मौसम की स्थिति और तकनीकी समस्याओं के कारण एक्सिओम–4 के प्रक्षेपण में कई बार देरी हुई। 25 जून को सफल प्रक्षेपण नासा द्वारा घोषित छठे निर्धारित प्रयास को चिह्नित करता है। इस मिशन में शुक्ला के साथ नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन भी हैं, जो कमांडर के रूप में कार्य करती हैं, साथ ही पोलैंड से मिशन विशेषज्ञ स्लावोज उज्नान्स्की–विस्नीव्स्की और हंगरी से टिबोर कापू भी हैं। एक्सिओम–4 मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पोलैंड और हंगरी के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है।

शुक्ला ने अपने संदेश में कहा कि नमस्कार, मेरे प्यारे देशवासियोंय 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, यह कमाल की राइड (यात्रा) थी। उन्होंने कहा कि इस समय हम साढ़े सात किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेले नहीं, (बल्कि) मैं आप सबके साथ हूं।

कश्मीर पर कुछ मत बोलना...57 देशों के सामने दहाड़ा भारत

नई दिल्ली (एजेन्सी)। जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ फैलाना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव प्रस्तुत करना पाकिस्तान की पुरानी आदत बन चुकी है। वो लगातार ऐसे प्रयास करता रहा है, जिनका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को गुमराह करना और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना होता है। तुर्की में हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पाकिस्तान ने ओआईसी का उपयोग करके कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप करवाने की कोशिश की। ओआईसी देशों ने भी कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष को दोहराते हुए कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों के इच्छाओं के अनुरूप कश्मीर के लोगों के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं।

हालांकि भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ ओआईसी को भी जमकर फटकार लगाई। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ओआईसी के पास इस मामले में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ओआईसी पाकिस्तान के प्रभाव में आकर कश्मीर को लेकर उसके बारे में अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दे रहा है। विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान में कहा कि आतंकवाद को राजकाज में बदल देने वाले पाकिस्तान द्वारा दिए गए ये बयान संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ओआईसी मंच के निरंतर दुरुपयोग को दर्शाते हैं। ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है– एक ऐसा तथ्य जो भारतीय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के वास्तविक खतरे को स्वीकार करने में ओआईसी बार–बार विफल रहा है जिसका सबसे हालिया सबूत पहलगाम हमले में देखने को मिला, यह तथ्यों के प्रति जानबूझकर की गई उपेक्षा को दर्शाता है।

विदेश मंत्रालय ने कहाआतंकवाद को राजकीय कौशल में तब्दील करने वाले पाकिस्तान के इशारे पर ये बयान संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ओआईसी मंच के निरंतर दुरुपयोग को दर्शाते हैं। ओआईसी के पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, जो भारत का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है– एक ऐसा तथ्य जो भारतीय संविधान में निहित है और यह अपरिवर्तनीय है। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया तुर्किये में ओआईसी के विदेश मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद आई है, जिसमें भारतीय मुसलमानों को 'सामाजिक रूप से हाशिए' पर धकेलने सहित कई मुद्दों पर नयी दिल्ली की आलोचना की गई। ओआईसी ने सिंधु जल संधि सहित भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया और सभी लंबित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यापक आधार वाली बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया।

पीएम मोदी बोले- कोई भारतीय नहीं भूलेगा कि कैसे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया

नई दिल्ली (एजेन्सी)। 25 जून 1975 की आधी रात को, भारत – एक युवा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र – जम गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर रोक लगा दी गई और संविधान को पूर्ण कार्यकारी शक्ति के साधन में बदल दिया गया। अगले 21 महीनों तक, भारत तकनीकी रूप से अभी भी एक लोकतंत्र था, लेकिन कुछ भी नहीं की तरह काम कर रहा था। आज 25 जून 2025 को आपातकाल के वो काले दिन को लगे 50 साल हो गये है। इस तिथि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान संविधान की भावना का कैसे उल्लंघन किया गया। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कई पोस्ट कर मोदी ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्याय में से एक है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को दबा दिया गया ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक

नई दिल्ली (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ मनाने का संकल्प लिया। कैबिनेट ने उन अनगिनत नागरिकों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने आपातकाल के दमनकारी शासन और भारतीय संविधान के सार को दबाने के उसके प्रयास के खिलाफ बहादुरी से खड़े हुए। यह स्वीकार करते हुए कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का क्षरण 1974 में ही नवनिर्माण आंदोलन और संपूर्ण क्रांति अभियान पर कार्रवाई के साथ शुरू हो गया था, कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक के दौरान दो मिनट का मौन भी रखा। इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को याद करने के अलावा, कैबिनेट ने कई प्रभावशाली विकास पहलों को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सत्र के दौरान लिए गए तीन महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। पुणे मेट्रो विस्तारः पुणे में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 3,626 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है, जिससे शहरी गतिशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास में वृद्धि होगी। संशोधित झरिया मास्टर प्लानः झारखंड के झरिया में भूमिगत कोयला आग की लंबे समय से चली आ रही समस्या को संबोधित करते हुए, प्रभावित समुदायों को राहत पहुंचाने और पर्यावरण संतुलन को बहाल करने के लिए 5,940 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी गई। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्रः कृषि के क्षेत्र में एक अनूठा कदम उठाते हुए, मंत्रिमंडल ने आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना के लिए 111 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। इस कदम से देश भर में आलू की खेती में नवाचार और उत्पादकता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2025 संविधान हत्या दिवस के 50 वर्ष पूरे होंगे – भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय जहां संविधान को नष्ट कर दिया गया, भारत के गणतंत्र और लोकतांत्रिक भावना पर हमला किया गया, संघवाद को कमजोर किया गया और मौलिक अधिकारों, मानव स्वतंत्रता और गरिमा को निलंबित कर दिया गया। 25 जून 1975 की आधी रात को, भारत – एक युवा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र – जम गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर रोक लगा दी गई और संविधान को पूर्ण कार्यकारी शक्ति के साधन में बदल दिया गया। अगले 21 महीनों तक, भारत तकनीकी रूप से अभी भी एक लोकतंत्र था, लेकिन कुछ भी नहीं की तरह काम कर रहा था। आज 25 जून 2025 को आपातकाल के वो काले दिन को लगे 50 साल हो गये है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, डॉ. महेंद्र सिंह पाल को गले लगाकर फूट-फूटकर रोए

हल्द्वानी (एजेन्सी) उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बुधवार को उत्तराखंड दौरे के दौरान भावनात्मक क्षणों में स्वास्थ्य बिगड़ गया। हल्द्वानी के आर्मी हेलीपैड पर स्वागत के बाद वह कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 1989 में संसद में साथ रहे डॉ. महेंद्र सिंह पाल का नाम बार–बार लिया। जैसे ही मंच से उतरे, उन्होंने डॉ. पाल को गले लगा लिया। दोनों के बीच पुरानी यादें साझा हुईं और इसी भावुक क्षण में दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। भावनाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि डॉ. पाल के गले लगते ही उपराष्ट्रपति खुद भी रोने लगे। यह दृश्य उपस्थित जनसमूह के लिए भी भावनात्मक क्षण बन गया। हालांकि, इसी दौरान उपराष्ट्रपति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वहां मौजूद चिकित्सकीय दल ने तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद धनखड़ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह के साथ राजभवन के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति का स्वास्थ्य फिलहाल स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में है। इस घटनाक्रम के बाद कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्थाएं और भी सख्त कर दी गई हैं। इस घटना ने यह दिखाया कि देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोग भी भावनाओं से अछूते नहीं होते। राजनीति के कठिन रास्ते पर पुराने साथियों की मुलाकात ने मानवीय संवेदनाओं को उजागर कर दिया।

खरगे ने थरूर पर साधा निशाना, बोले, कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है

नयी दिल्ली (एजेन्सी) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किए जाने पर पार्टी के भीतर मचा बवाल बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज थरूर पर तीखा हमला बोला है। खरगे ने कहा, हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है।ष कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से थरूर पर यह अब तक का सबसे कड़ा तंज माना जा रहा है। इससे पहले भी थरूर के कई पार्टी सहयोगी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी टिप्पणियों को लेकर उन पर कटाक्ष कर चुके हैं। खरगे की यह टिप्पणी शशि थरूर के एक लेख को लेकर आई है। इस लेख में थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया था। द हिंदू अखबार में प्रकाशित इस लेख में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और बातचीत करने की इच्छा वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन इसे और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। उनकी इन टिप्पणियों ने कांग्रेस पार्टी को नाराज कर दिया है। इससे कांग्रेस नेतृत्व और पूर्व राजनयिक थरूर के बीच की खाई और गहरी हो गई है। जहाँ मुख्य विपक्षी दल (कांग्रेस) सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, वहीं थरूर अपनी ही पार्टी की आवाज को चुनौती देते दिख रहे हैं।

मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने स्पष्ट किया कि उनका लेख बीजेपी में शामिल होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता, हित और भारत के लिए खड़े होने का बयान है। कांग्रेस ने कल ही थरूर की इस टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से कहा, यह उनकी अपनी राय हो सकती है, यह कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है. यह कांग्रेस का विचार नहीं हैं, क्योंकि हमने अपने विचार सबूतों और प्रमाणों के साथ पेश किए हैं। आज मल्लिकार्जुन खरगे ने शशि थरूर की अंग्रेजी की प्रशंसा करते हुए व्यंगात्मक लहजे में कहा, मैं अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ सकता। उनकी भाषा बहुत अच्छी है, इसलिए हमने

उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनाया है। कांग्रेस प्रमुख ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के बाद, पूरा विपक्ष सेना के साथ खड़ा है। हमने कहा कि देश पहले आता है, पार्टी बाद में. कुछ लोगों को लगता है कि श्मोदी पहले, देश बाद में. हम क्या कर सकते हैं? खरगे का यह बयान सीधे तौर पर थरूर के मोदी की तारीफ करने पर कटाक्ष था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय हितों से ऊपर व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

सीएम फडणवीस बोले, भारत का लोकतंत्र इसलिए बचा क्योंकि, लोगों ने आपातकाल का विरोध किया

मुंबई (एजेन्सी) मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भारत का लोकतंत्र उन लोगों के संघर्ष के कारण बचा है, जिन्होंने आपातकाल लागू किए जाने का विरोध किया था। आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए उन्होंने कहा कि जब संविधान, लोकतंत्र और कई संस्थाओं को कुचल दिया गया था, तो इसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा, "जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जी–जान से लड़ाई लड़ी। उन्होंने आपातकाल लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विरोध किया।वह 25 जून 1975 को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने की 50वीं बरसी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। फडणवीस ने कहा, "आज का दिन उन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का है, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी।

सम्पादकीय

नई ऊंचाई पर भारत-आस्ट्रेलिया संबंध

मेरी भारत यात्रा के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते आज नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ व्यापार और निवेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे बीच उस गहरे जुड़ाव को भी रेखांकित करते हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच वर्षों से कायम हैं। मेरा अनुभव है कि दो देशों के बीच रिश्तों के लिए वक्त, धैर्य और एक–दूसरे को समझने की इच्छा भी चाहिए होती है। हमें यह भी देखना होता है कि मौजूदा परिस्थितियां किस तरह हमारे सोचने के तरीके और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और विशेष रूप से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य सरकार ने भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। गत वर्ष भारत में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति इसका प्रमाण है कि भारत की हमारे लिए कितनी ज्यादा अहमियत है। इस वर्ष के आरंभ में हमारे व्यापार और निवेश मंत्री जो स्जाकस और (प्रीमियर) पीटर मालिनौस्कस की भारत यात्रा इसका उदाहरण है। हम भारत के साथ मिलकर ऐसे कदम उठाना चाहते हैं, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हों। शिक्षा में साझेदारी, हरित अर्थव्यवस्था में निवेश, पानी के बेहतर प्रबंधन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान या फिर हवाई, कृषि–खाद्य और पर्यटन की बात हो, ऑस्ट्रेलिया और खासकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया भरोसेमंद साझेदार मान सकता है। दीर्घकालिक निवेश के लिए भी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया एक विश्वसनीय और लाभकारी साझेदार है। हम अपने यहां शांति और स्थिरता को बनाए रखने के साथ गर्म होती जलवायु की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हरित ऊर्जा, निर्माण और कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में नए समाधानों की तलाश में जुटे हैं। हमारे यहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं, जो हमारे समाज की विविधता को और अधिक बढ़ाते हैं। ये लोग हमारे रिश्तों की मजबूत नींव हैं। शिक्षा के जरिये भी हमारे रिश्ते और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में विदेशी छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। मेरी हालिया यात्रा का एक लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र से भारत के जुड़ाव को और मजबूत बनाना भी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की अर्थव्यवस्थाएं कई मामलों में एक–दूसरे की पूरक हैं, खासकर अंतरिक्ष, सूचना तकनीक, एआइ और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। ये क्षेत्र न सिर्फ भारतीय युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों में नौकरियों और नए आविष्कारों के दरवाजे भी खोल रहे हैं। हाल में ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स नई दिल्ली में थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया–भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं सालगिरह मनाई, जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र में हमारी साझेदारी की नींव है। 2022 के ऑस्ट्रेलिया–भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने दोनों देशों के बीच व्यापार को नई रफ्तार दी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत अब इसे व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी से जुड़े करार भी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें संयुक्त रूप से विकसित किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया–भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष नई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करता है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर पूरकता ऑस्ट्रेलिया और भारत को एक–दूसरे का स्वाभाविक साझेदार बनाती है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक संसाधन हैं, जो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन दिनों दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत की अर्थव्यवस्था भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। हमारे यहां स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर आधारित उद्योगों में काफी प्रगति हुई है। आस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट आफ मशीन लर्निंग जैसे विश्वस्तरीय संस्थान हमारे यहां हैं। हमने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार परिसर स्थापित किए हैं, जो कई विश्वस्तरीय कंपनियों और स्टार्टअप का घर हैं। ये सभी विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा परिसरों से कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित हैं।

जब जेल जैसा बन गया था देश, आपातकाल की बुरी यादें

केसी त्यागी। आज से 50 वर्ष पहले देश पर थोपा गया आपातकाल एक ऐसा कालखंड है, जो गांधी, नेहरू, पटेल आदि के परिश्रम से बनी कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी के पदमोह का शिकार बना। उन्होंने तानाशाही, ज्यादती, निरंकुशता के बलबूते लोकतंत्र एवं स्वाधीनता पर बेरहमी से प्रहार किया। यह राजनीतिक अपराध था। इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल के अध्याय की शुरुआत 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय से प्रारंभ होती है। 1971 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली में इंदिरा का मुकाबला विपक्षी समाजवादी नेता राजनारायण से था। इंदिरा गांधी विजयी होती हैं, पर राजनारायण उनकी जीत को अदालत में चुनौती देते हैं। उन्होंने उन पर अपने निजी सचिव एवं सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर को चुनाव एजेंट बनाने, स्वामी अद्वैतानंद को 50 हजार रुपये घूस देकर निर्दलीय प्रत्याशी बनाने, वायुसेना विमानों का इस्तेमाल करने, चुनाव में डीएम और एसपी की अनुचित मदद लेने, वोटरों को शराब, कंबल बांटने आदि आरोप लगाए। जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती गांधी का चुनाव रद कर छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया। उनके फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी और उन्हें पदोन्नति का भी प्रलोभन दिया गया था। वे टस से मस नहीं हुए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद नैतिकता का तकाजा था कि इंदिरा इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करतीं, पर 12 जून को ही भीड़ ने उनके आवास के समक्ष जस्टिस सिन्हा को सीआइए एजेंट बताकर नारेबाजी की। तब गुजरात और बिहार में कांग्रेस सरकारों के खिलाफ जारी आंदोलन को जेपी दिशा दे रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आने पर इंदिरा के त्यागपत्र की मांग लेकर विपक्षी दल लामबंद होने लगे और 25 जून को रामलीला मैदान, दिल्ली में सभा रखी गई। यह सभा 20 को होनी थी, पर जेपी के दिल्ली आने के पहले ही यहां आने वाली उड़ानें अचानक रद कर दी गईं। अंततः सभा 25 जून को हुई। मैं लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में वहां था। मंच का संचालन जनसंघ, जो बाद में भाजपा बनी, नेता मदनलाल खुराना कर रहे थे। जेपी ने इंदिरा सरकार को अवैध बताया और उनके इस्तीफे की मांग की तथा सरकारी कर्मियों एवं पुलिस वालों को 'असंवैधानिक सरकार' के आदेश न मानने को कहा। उन दिनों इंदिरा के बेटे संजय गांधी की सक्रियता बढ़ गई थी। वे आरके धवन, चौधरी बंसीलाल आदि से मिलकर विरोधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जोर दे रहे थे। कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व युवा नेता चंद्रशेखर कर रहे थे, जो जेपी से संवाद के समर्थक थे। उनके प्रयासों से जेपी की दो मुलाकातें श्रीमती गांधी से हुईं, पर वे बेनतीजा रहीं। इंदिरा प्रेस के स्वतंत्र रुख से खफा थीं। 25 जून को रात 11रू45 पर आपातकाल की घोषणा वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर कराए गए और अगली सुबह 6 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर उस पर मुहर लगाई गई। इंदिरा ने सुबह रेडियो संदेश दिया, 'भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की जरूरत नहीं है...।' विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला 25 जून की मध्यरात्रि से कायम हो गया था। इन नेताओं की लिस्ट संजय गांधी और साथियों ने बनाई। तब अदालतों को भी निर्देश था कि बंदियों को जमानत न दी जाए। आपातकाल के तहत अदालत जाने के अधिकार के साथ नागरिकों के कई मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। 25 जून की रात या फिर अगले दिन गिरफ्तार होने वालों में जेपी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, बीजू पटनायक, पीलू मोदी और राजनारायण आदि थे। यह सिलसिला कायम रहा। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले अखबारों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई।

ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद पाकिस्तान की 'नोबेल डिप्लोमेसी' पर गिरी गाज

नीरज कुमार दुबे

जमीयत उलेमा–ए–इस्लाम (जेयूआई–एफ) के प्रमुख वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान ने मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। फजल ने पार्टी की एक बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप का शांति का दावा झूठा साबित हुआ हैय नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ट्रंप की हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक और दोनों के साथ में भोजन करने से 'पाकिस्तानी शासकों को इतनी खुशी हुई' कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश कर दी। फजल ने सवाल किया, ''ट्रंप ने फलस्तीन, सीरिया, लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों का समर्थन किया है। यह शांति का संकेत कैसे हो सकता है?'' उन्होंने कहा, ''जब अमेरिका के हाथों पर अफगानों और फलस्तीनियों का खून लगा हो, तो वह शांति का समर्थक होने का दावा कैसे कर सकता है? वहीं पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने 'एक्स' पर लिखा, ''चूंकि ट्रंप अब संभावित शांतिदूत नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं।

पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अपने अमेरिका दौरे पर इतराते हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किये हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान एक बड़े राजनयिक संकट में फंस गया और उसे ऐसा डिप्लोमेटिक यूटर्न लेना पड़ा जोकि राजनय के इतिहास में हमेशा के लिए हास्यास्पद घटना के तौर पर देखा जायेगा। हम आपको बता दें कि जैसे ही पाकिस्तान ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित करने की घोषणा की उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के तीन परमाणु संयंत्रों पर बंकर बलास्टर बम बरसवा कर मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा पैदा कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति पैदा हो गयी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक म्हह वद लवनत बिम वाली अंग्रेजी कहावत का संदर्भ देकर भी उड़ाया जाने लगा। हम आपको बता दें कि इस कहावत का हिंदी में मतलब है शर्मिंदा होना या मूर्ख दिखना। ईरान पर अमेरिकी हमलों से पहले डोनाल्ड ट्रंप को विश्व का शांति दूत करार दे रहे पाकिस्तान ने अमेरिकी बमवर्षक विमानों के हमले की निंदा वाला बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमले ष्अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघनष हैं। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत ईरान को आत्मरक्षा का वैध अधिकार है।

हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान के कुछ नेताओं और प्रमुख हस्तियों ने ईरान के तीन परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमले के बाद सरकार से 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। इसलिए देखना होगा कि क्या पाकिस्तान सरकार नोबेल पुरस्कार समिति से की गयी अपनी सिफारिश को वापस लेती है या नहीं? हालांकि उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हस्ताक्षर वाला अनुशंसा–पत्र नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेजा जा चुका है। लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज परमाणु केन्द्रों पर हमले किए जाने के बाद इस फैसले को लेकर पाकिस्तानी नागरिकों, संगठनों और मीडिया की ओर से आपत्तियां आने लगी हैं। पाकिस्तान के कई प्रमुख राजनेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार से नवीनतम घटनाक्रम के मद्देनजर अपने फैसले की समीक्षा करने की मांग की है।

जमीयत उलेमा–ए–इस्लाम (जेयूआई–एफ) के प्रमुख वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान ने मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। फजल ने पार्टी की एक बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप का शांति का दावा झूठा साबित हुआ हैय नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ट्रंप की हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक और दोनों के साथ में भोजन करने से 'पाकिस्तानी शासकों को इतनी खुशी हुई' कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश कर दी। फजल ने सवाल किया, ''ट्रंप ने फलस्तीन, सीरिया, लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों का समर्थन किया है। यह शांति का संकेत कैसे हो सकता है?'' उन्होंने कहा, ''जब अमेरिका के हाथों पर अफगानों और फलस्तीनियों का खून लगा हो, तो वह शांति का समर्थक होने का दावा कैसे कर सकता है? वहीं पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने 'एक्स' पर लिखा, ''चूंकि ट्रंप अब संभावित शांतिदूत नहीं रह गए हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जानबूझकर एक अवैध युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए पाकिस्तान सरकार को अब नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश पर पुनर्विचार करना चाहिए, उसे रद्द करना चाहिए!'' उन्होंने कहा कि ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की 'युद्ध लॉबी' के जाल में फंस गए हैं और अपने राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं।

इसके अलावा, पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) के सांसद अली मुहम्मद खान ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर ''पुनर्विचार करें'' लिखा। उन्होंने ''ईरान पर अमेरिकी हमले और गाजा में इजराइल द्वारा की गई हत्याओं के लिए निरंतर अमेरिकी समर्थन'' होने का दावा किया। साथ ही, अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत मलीहा लोधी ने अपनी सरकार के इस कदम को ''दुर्भाग्यपूर्ण'' करार दिया और कहा कि यह जनता के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मारियाना बाबर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ''आज पाकिस्तान भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है''। उन्होंने ट्रंप के नाम की सिफारिश वाली पाक सरकार की पोस्ट को साझा करते हुए यह बात कही। इसके अलावा, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता फातिमा भुट्टो ने कहा, ''क्या पाकिस्तान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके (ट्रंप के) नाम की सिफारिश वापस लेगा?श्श वहीं, पत्रकार तलत हुसैन ने कहा कि ष्यह मानसिक गुलामी और अमेरिकी स्वीकृति पाने की बेताबी को दर्शाता है।ष इसके अलावा, राजनीतिक विश्लेषक मुशर्रफ जैदी ने कहा, ष्जनता के बीच असंगति को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है। यह पाकिस्तान की नैतिक स्थिति को कमजोर करता है और इसे सौदेबाजी वाली कूटनीति के रूप में पेश करता है। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर #NobelForWar vkSj #TrumpNominationShame जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। इस तरह ट्रंप के नाम का नोबेल के लिए सिफारिश कर पाकिस्तान ने जो कूटनीतिक उपलब्धि हासिल करनी चाही थी वह अब एक बड़ी चूक साबित हो चुकी है। बहरहाल, शहबाज शरीफ सरकार भले अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने के लिए तरह–तरह की रणनीति अपना रही है, लेकिन उसकी सारी चालें उलटी पड़ती जा रही हैं। ट्रंप को पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ने ही शांति पुरुष कहा और ईरान पर हमले के ठीक बाद जिस तरह इस्लामाबाद ने बड़ी तेजी दिखाते हुए निंदा वाला बयान जारी कर दिया उससे पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया है कि पाकिस्तान की बातों का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और वह किसी का सगा नहीं है। साथ ही, पाकिस्तान में जिस प्रकार अपनी सरकार और सेना की ओर से ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश का विरोध किया जा रहा है उसको देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान सरकार अपना फैसला वापस लेती है?

यह देखना भी रुचिकर होगा कि पाकिस्तान सरकार की सिफारिश पर नोबेल शांति पुरस्कार समिति का क्या रुख रहता है? जमीयत उलेमा–ए–इस्लाम (जेयूआई–एफ) के प्रमुख वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान ने मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले। फजल ने पार्टी की एक बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप का शांति का दावा झूठा साबित हुआ हैय नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ट्रंप की हाल में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बैठक और दोनों के साथ में भोजन करने से 'पाकिस्तानी शासकों को इतनी खुशी हुई' कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने की सिफारिश कर दी। फजल ने सवाल किया, ''ट्रंप ने फलस्तीन, सीरिया, लेबनान और ईरान पर इजराइल के हमलों का समर्थन किया है। यह शांति का संकेत कैसे हो सकता है?

भारत समेत पूरी दुनिया की इस पर है नजर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुल्लाशाही(मुल्लाओं यानी मजहबी नेताओं का शासन) को आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत का प्रलोभन देकर परमाणु शक्ति और मिसाइल तकनीक की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के सौदे पर तैयार करने में लगे थे। तभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यकायक नाटकीय तरीके से हमला करके ईरान की सेना और परमाणु शक्ति के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया। हमले पर ट्रंप की आरंभिक प्रतिक्रियाएं देखकर लगा कि अपने कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजरायल का कूद पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर जैसे ही उन्हें इजरायली हमलों की नाटकीय कामयाबी का अहसास हुआ तो उन्होंने इजरायल को रोकने की जगह उसकी कामयाबी की बात करना और ईरान से समर्पण करने की मांग करना शुरू कर दिया।

शिवकांत शर्मा

पश्चिम एशिया में धौंस की कूटनीति का एक खतरनाक दौर शुरू हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुल्लाशाही(मुल्लाओं यानी मजहबी नेताओं का शासन) को आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत का प्रलोभन देकर परमाणु शक्ति और मिसाइल तकनीक की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के सौदे पर तैयार करने में लगे थे। तभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यकायक नाटकीय तरीके से हमला करके ईरान की सेना और परमाणु शक्ति के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया। हमले पर ट्रंप की आरंभिक प्रतिक्रियाएं देखकर लगा कि अपने कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजरायल का कूद पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर जैसे ही उन्हें इजरायली हमलों की नाटकीय कामयाबी का अहसास हुआ तो उन्होंने इजरायल को रोकने की जगह उसकी कामयाबी की बात करना और ईरान से समर्पण करने की मांग करना शुरू कर दिया। एक तरफ वे ईरान को दो हफ्तों का समय देने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ दिएगो गार्सिया में अपने बी2 बमवर्षक विमानों को हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। झांसा देकर वार करना ट्रंप की शैली है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक 'द आर्ट आफ द डील' में किया है। ईरान को दो हफ्तों के झांसे में रखकर फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु संयंत्रों पर बम बरसा दिए। ट्रंप ने फोर्डो समेत ईरान के परमाणु केंद्रों को ध्वस्त करने का दावा करते हुए धमकी दी है कि यदि ईरान अब भी समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो और विनाशकारी हमले किए जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भी ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व के लिए गंभीर खतरा बताया। ईरान ने जवाब में इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद वहां लोग जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए तो यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे कामयाब घड़ी है, पर अमेरिका के भीतर इस हमले को लेकर जनमत बुरी तरह बंटा हुआ है। दूसरे देश पर हमला करने के लिए राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद का अनुमोदन लेना जरूरी होता है। इराक पर हमले से पहले दोनों बुश राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस का अनुमोदन लिया था। इसलिए अमेरिकी सांसदों–सीनेटरों का एक वर्ग ट्रंप के लड़ाई में उतरने से नाराज है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का 'मागा' धड़ा इससे नाराज है कि उन्होंने अमेरिका को युद्धों में न उलझाने के चुनावी वादे को तोड़कर इजरायल की लड़ाई में पांव फंसा लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। यूरोप और पश्चिम एशिया के देश जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम का खतरा कम होने और समझौते की संभावना प्रबल होने का स्वागत करेंगे, वहीं अमेरिकी हमले की वैधता की निंदा होगी। रूस और चीन समेत दुनिया के दूसरे देश कूटनीति का रास्ता छोड़कर दूसरे देश की प्रभुसत्ता के उल्लंघन की निंदा करेंगे। अमेरिका–इजरायल के साथ–साथ ईरान के साथ भी घनिष्ठ संबंध होने के कारण भारत के लिए यह हमला धर्मसंकट खड़ा करता है। भारत यह तो चाहेगा कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोका जाए, पर उसके लिए उसकी प्रभुसत्ता का अतिक्रमण करने की हिमायत कभी नहीं कर सकता। दिलचस्प यह भी है कि ईरान 1968 से ही परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी का सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी उसकी परमाणु गतिविधियों पर नजर रख सकती है। जबकि इजरायल परमाणु शक्ति होते हुए भी एनपीटी का सदस्य नहीं है। यानी एक तरह से एक 'चोर' जज और सिपाही बना बैठा है। इस संदर्भ में इजरायल का तर्क रहा है कि दशकों से परमाणु शक्ति होने के बावजूद उसने न कभी किसी दूसरे देश को मिटाने की धमकी दी और न ही परमाणु प्रसार किया है। जबकि ईरान की मुल्लाशाही अक्सर इजरायल के सर्वनाश की बात करती रहती है। हालांकि यह तर्क ईरान से अधिक तो पाकिस्तान पर लागू होता है, जिसके प्रसार की बदौलत आज ईरान परमाणु शक्ति बनने के कगार पर है। फिर भी अमेरिका ने वैसी तत्परता पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने में नहीं दिखाई जैसी वह ईरान को रोकने में दिखा रहा है। अब भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि ईरानी मुल्लाशाही अमेरिका के हमले का कब और क्या जवाब देती है। उसने इजरायल पर हमला बोल ही दिया। वैसे उनके पास तीन विकल्प हैं। इराक, यमन और लेबनान में फैले हमास और हाउती जैसे शिया मिलिशिया से अमेरिकी ठिकानों और जहाजों पर हमले कराए और होरमुज जलसंधि में बारूदी सुरंगे बिछाकर उसे बंद कर दे। वह खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को भी निशाना बना सकता है, जिससे तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हालांकि सऊदी और यूएई ने लाल सागर तटों तक तेल और गैस की पाइपलाइनें बिछा कर सप्लाई का वैकल्पिक रास्ता बना रखा है, लेकिन बाजार जोखिम और धारणा के आधार पर दाम तय करते हैं। 1979–80 में इस्लामी क्रांति होने भर से तेल के दाम तिगुने हो गए थे। यदि ऐसा हुआ तो भारत ही नहीं पूरे विश्व की आर्थिकी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरा विकल्प अमेरिका की शर्तें मानकर समझौता करने का है, जिसके लिए ईरानी लोग शायद सरकार को कभी माफ न करें, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम राजशाही के जमाने का है और उसे ईरान के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। तीसरा विकल्प अमेरिका और इजरायल के वार झेलते हुए सद्दाम हुसैन और बशर अल–असद की तरह संकट की घड़ी टलने का इंतजार करने का है। ईरान के पास साढ़े तीन लाख सेना के साथ ही लगभग उतनी ही बड़ी तादाद में क्रांतिकारी गार्ड और बसीज स्वयंसेवकों के दस्ते हैं, जिनके सहारे वे संभावित विद्रोह को दबाए रख सकते हैं। ईरान में राजशाही को समाप्त हुए दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं। इसलिए उनका जनाधार नहीं बचा है। राजशाही के विरोधी वामपंथी मुजाहिदीन–ए–खल्क की छवि ईरान–इराक युद्ध में इराक के समर्थन के कारण खराब है और कुर्द और बलोच गुटों का जनाधार केवल सीमावर्ती प्रांतों तक सीमित है। प्रबल और संगठित विपक्ष के न रहने के कारण मुल्लाशाही के लिए इजरायली–अमेरिकी हमलों से जगे राष्ट्रवाद की भावना के सहारे सत्ता में बने रहना कठिन नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की मुल्लाशाही(मुल्लाओं यानी मजहबी नेताओं का शासन) को आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत का प्रलोभन देकर परमाणु शक्ति और मिसाइल तकनीक की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देने के सौदे पर तैयार करने में लगे थे। तभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यकायक नाटकीय तरीके से हमला करके ईरान की सेना और परमाणु शक्ति के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया। हमले पर ट्रंप की आरंभिक प्रतिक्रियाएं देखकर लगा कि अपने कूटनीतिक प्रयासों के बीच इजरायल का कूद पड़ना उन्हें अच्छा नहीं लगा, पर जैसे ही उन्हें इजरायली हमलों की नाटकीय कामयाबी का अहसास हुआ तो उन्होंने इजरायल को रोकने की जगह उसकी कामयाबी की बात करना और ईरान से समर्पण करने की मांग करना शुरू कर दिया। एक तरफ वे ईरान को दो हफ्तों का समय देने की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ दिएगो गार्सिया में अपने बी2 बमवर्षक विमानों को हमलों के लिए तैयार कर रहे थे। झांसा देकर वार करना ट्रंप की शैली है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक 'द आर्ट आफ द डील' में किया है। ईरान को दो हफ्तों के झांसे में रखकर फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु संयंत्रों पर बम बरसा दिए। ट्रंप ने फोर्डो समेत ईरान के परमाणु केंद्रों को ध्वस्त करने का दावा करते हुए धमकी दी है कि यदि ईरान अब भी समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो और विनाशकारी हमले किए जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भी ट्रंप के सुर में सुर मिलाते हुए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व के लिए गंभीर खतरा बताया। ईरान ने जवाब में इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद वहां लोग जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए तो यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे कामयाब घड़ी है, पर अमेरिका के भीतर इस हमले को लेकर जनमत बुरी तरह बंटा हुआ है। दूसरे देश पर हमला करने के लिए राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद का अनुमोदन लेना जरूरी होता है। इराक पर हमले से पहले दोनों बुश राष्ट्रपतियों ने कांग्रेस का अनुमोदन लिया था।

दुनिया की सबसे भयानक बीमारी का बेस्ट इलाज भारतीयों के पास है!

83 वर्ष के रिटायर बैंकर मर्विन मार्कस के पास इन दिनों एक नया मित्र है। और वर्तमान में इस नए मित्र की मित्रता महज 23 लोगों के साथ ही है। इसका नाम है 'मीला', यह ऐसा ही है जैसा आपने पहले 'एलेक्सा' सुना था। यह नया दोस्त फिलहाल पायलट तौर पर अध्ययन के लिए अमेरिका में वरिष्ठजनों के सामुदायिक आवास के निवासियों के साथ है। मीला अकेले रहने वाले लोगों के साथ चौट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक साथी है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य यूजर्स के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। अतरू यह ना सिर्फ एक ऐसी साथी है, जिससे आप जब चाहो, जिस विषय पर चाहो बात कर सकते हो, बल्कि बेहद सहानुभूतिपूर्ण भी है। यदि आप किसी बात पर हताश हो तो मीला पीछे से कहेगी कि 'यह समझ आता है'। वहां से कुछ सौ किलोमीटर दूर कनाडा में 57 वर्षीय ब्रेन फर्नांडीज 'को–हाउसिंग सिस्टम' बनाकर संयुक्त परिवार प्रणाली को दोहराने की योजना बना रहे हैं, जहां भिन्न पृष्ठभूमि के लोग साथ रहें व देखें कि मिलकर कितने बेहतर तरीके से उम्रदराज हो सकते हैं। उन्होंने बचपन भारत में, खासकर संयुक्त परिवार में बिताया। वो सिंगल हैं, संतान नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि उनके जैसे लोग ओंटेरियो में उनकी 17 एकड़ की संपत्ति में रहें, जो उन्होंने खासकर एलजीबीटीक्यू वर्ग के 40 वरिष्ठजनों के लिए तय की है। वरिष्ठजनों के लिए दीर्घकालिक देखभाल सुविधा में लंबे समय काम के दौरान फर्नांडीज ने देखा कि उनसे मिलने कभी कोई नहीं आता, इसलिए उन्हें इस समुदाय के बुजुर्गों की चिंता थी। सोशल एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो ये स्टडी करते हैं कि सामाजिक कारक कैसे लोगों की हेल्थ पर असर डालते हैं और सामाजिक–आर्थिक स्तर, नस्ल, लिंग, पड़ोस का वातावरण, सोशल नेटवर्क, सामाजिक नीतियों का कैसा असर पड़ा है। उनका कहना है कि लोग तब सबसे अच्छा महसूस करते हैं, जब वो ऐसे सामाजिक मेलमिलाप में रहें, जहां उन्हें स्वच्छंदता भी मिले। मुझे नहीं लगता, इसे समझने के लिए 'सोशल एपिडेमियोलॉजिस्ट' जैसे आकर्षक नाम की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने पहले ही ऐसा कुछ बनाया, जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जब परिवार में ज्यादा बच्चे होते थे तो एक परिजन सभी के टूथब्रश पर मटर के दाने बराबर टूथपेस्ट रखता और निगरानी भी करता कि सभी प्रतिदिन नहाकर, साफ कपड़े पहनें। जब परिवार में बहुत से बुजुर्ग होते तो बीच की उम्र का एक सदस्य (पुरुष या महिला) वो सारे काम सुनिश्चित करता जो बच्चों के लिए थे। संयुक्त परिवारों में बुजुर्ग सामाजिक मेलजोल में रहते हैं, उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी मर्जी व जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। जब मैंने कमाना शुरू किया तो परिवार में बच्चों को मेरी गिफ्ट बॉम्बे (अब मुम्बई) के विले पार्ले से लाए पार्ले के ब्रोकन ग्लूकोज बिस्किट होते थे और नानाजी के लिए कुछ किलो किस्मी टॉफी होती थीं, जिसे वो गाल में दबाकर मिनटों चूसा करते थे। आज कुछ लोग कह सकते हैं, 'देखो, कैसे बच्चे जैसे कैंडी चूस रहे हैं', पर तब हमें उनका बच्चों जैसा व्यवहार और बिना दांतों की मुस्कान बहुत पसंद थी।

उन्हें कभी भी डायबिटीज नहीं हुई, क्योंकि वो मंदिर में परिक्रमा करते रहते थे, चलते रहते थे, ताकि अगले जन्म के लिए पुण्य कमा सकें, यदि ऐसा कुछ होता है तो। घर में कुछ बच्चे उन्हें मंदिर ले जाते और जब नानी कहतीं कि 'नाना को ले आओ, खाना तैयार है, वो वहां मंदिर में ऐसे बैठे हैं, मानो भगवान ही उनके लिए खाना बनाने जा रहा है।' तो बच्चे उन्हें लेने जाते थे। इस बात में हताशा नहीं थी। क्योंकि दोनों ने वही चुना जो उन्हें अच्छा लगता था, नाना ने मंदिर चुना और नानी ने रसोई। मंदिर से लौटते हुए वो कहानियां, ऑफिस के पुराने किस्से सुनाते, फिर भले ही उस उम्र में वह हमारे समझ नहीं आते हों। लेकिन नानाजी जानते थे कि उनका अनुभव तीसरी पीढ़ी को दिया जा रहा था। फंडा यह है कि अकेलापन निरूसंदेह दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। एआई और 'को–हाउसिंग सिस्टम' हमारी उस संयुक्त परिवार संस्कृति के आसपास भी नहीं आ सकता, जैसी बुजुर्गों ने अपनाई थी। आपको नहीं लगता कि हमें हमारी जड़ों की ओर लौटना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए? संयुक्त परिवारों में बुजुर्ग सामाजिक मेलजोल में रहते हैं, उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता है।

अब कमेटी की निगरानी में होगी खाद की बिक्री

मनमाने दामों पर हो रही खाद की बिक्री पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाया

बाराबंकी (संवाददाता)। मनमाने दामों पर हो रही खाद की बिक्री पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कड़ा रुख अपनाया है। गड़बड़ी रोकने के लिए खाद बिक्री की निगरानी के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तहसीलवार टीमें गठित की गई है। इसके साथ ही कृषि विभाग को निर्देश दिया गया है कि खाद की बिक्री कर्मचारियों की मौजूदगी में ही कराई जाए। खाद की जमाखोरी रोकने के लिए रोस्टरवार ड्यूटी लगाकर सहकारी समितियों को संचालित कराने का निर्देश भी दिया गया है। खाद बिक्री में निजी दुकानदारों द्वारा बरती जा रही मनमानी व अवैध वसूली का संज्ञान लेते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी ने खाद वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने बताया कि डीएम ने तहसीलवार एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की है। साथ ही ब्लॉक स्तर पर संबंधित सहायक विकास अधिकारी कृषि व सहकारिता को पर्यवेक्षीय अधिकारी नामित किया गया है। न्याय पंचायत स्तर पर उर्वरक बिक्री केंद्रों पर कृषि विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में खाद की बिक्री किए जाने का निर्देश भी दिया गया है।

बताया कि जांच के दौरान बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध स्टॉक का पीओएस मशीन सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई विक्रेता इसमें गड़बड़ी का दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ सीधे केस दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि कि वह अपने–अपने प्रतिष्ठान पर रेट, स्टाक बोर्ड अवश्य लगाए और बिना किसी टैग के निर्धारित मूल्य पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराते हुए उन्हें इसकी रसीद भी दे। उपलब्धता की निगरानी को खुला कंट्रोल रूम किसानों को खाद मिलने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। कोई भी किसान कंट्रोल रूम के नंबर 9116295764 पर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उर्वरक संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकता है। गड़बड़ी रोकने के लिए खाद बिक्री की निगरानी के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तहसीलवार टीमें गठित की गई है।

महादेवा में लगने वाले श्रावण मास मेले की तैयारियां तेज

बाराबंकी (संवाददाता)। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में श्री लोधेश्वर धाम महादेवा में लगने वाले श्रावण मास मेले की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने मेला कराने वाले अधिकारियों, कमर्चारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्यों का निर्वहन जिम्मेदारी से करें जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए।डीएम ने कहा कि बैरिकेडिंग के कार्यों की व्यवस्था सुरक्षा मानकों को दृष्टिगत रखते हुए की जाए। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग की बल्लियों के बीच में लोहे की मजबूत जाली का प्रयोग होना चाहिए। दूर–दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग चयनित स्थलों पर की जाए। उन्होंने एसडीएम रामनगर को 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास मेला को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया।

18 करोड़ से बदलेगी 615 गांवों की तस्वीर, बनेंगे स्वच्छ

बाराबंकी (संवाददाता)। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जिले के 615 गांवों का चयन किया गया था। इसके लिए करीब 18 करोड़ रुपये की कार्ययोजना को शासन ने स्वीकृति देते हुए पहले चरण में एक करोड़ 80 लाख रुपये की धनराशि भी जारी कर दी है। इसके माध्यम से इन गांवों को स्वच्छ व सुंदर बना कर उनकी तस्वीर बदली जाएगी।सात माह पहले स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत चयनित 615 गांवों में योजना के तहत कार्य कराने के लिए करीब 18 करोड़ रुपये की प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। लेकिन धनराशि की स्वीकृति न मिल पाने के कारण स्वच्छता से जुड़े कार्य शुरु नहीं हो पा रहे थे। बीते दिनों शासन ने योजना को स्वीकृत करते हुए पहले चरण में होने वाले कार्य के लिए करीब 1.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है।स्वीकृत धनराशि से चिह्नित गांवों में आरआरसी सेंटरों का निर्माण, कूड़ा ढोने के लिए ई–रिक्शा की खरीद, एक जगह कूड़ा एकत्रित करने के लिए डस्टबिन की खरीद, जलनिकासी के लिए नालियों का निर्माण, सोंकपिट, खाद के गड्ढे, फिल्टर चौंबर आदि कार्य कराए जाएंगे।

39 गांवों पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा

बाराबंकी (संवाददाता)। बरसात शुरू होने के साथ ही सरयू नदी की बाढ़ का खतरा तहसील रामनगर के 39 गांवों पर मड़राने लगा है। रामनगर तहसील प्रदेश की 118 अति संवेदनशील बाढ़ प्रभावित तहसीलों में शामिल है। इसके दृष्टिगत ही 26 जून को मॉकड्रिल कर तटवर्तीय गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को बाढ़ से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। रामनगर तहसील के 39 गांवों की करीब 32 हजार आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। इनमें सात गांव ऐसे हैं जो हाई अलर्ट श्रेणी में आते हैं। इन गांवों में कटान का खतरा नदी में पानी बढ़ने के साथ ही शुरू हो जाता है। पिछले साल नदी की भीषण काटन से बबुरी, केदारीपुर व बेलहरी के 141 घर कटकर नदी में समा गए थे। 72 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन भी नदी में कट गई थी।

पिसावां के प्रेमपुर गांव के बाहर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में फैली दहशत

पिसावां (सीतापुर) (संवाददाता)। क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के खेतों में सोमवार को तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को ताजा पगचिह्न मिले हैं। टीम ने तेंदुआ होने की पुष्टि करते हुए लोगों सतर्क रहने की सलाह दी है।प्रेमपुर निवासी उमाकांत ने बताया कि वह सोमवार देर शाम खेतों की ओर गए थे, तभी तेंदुआ दिखा। वह भागकर गांव पहुंचे और ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद तमाम ग्रामीण लाठी–डंडे लेकर वहां पहुंचे। सूचना पर वनकर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग की, लेकिन वन्यजीव की लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकी। मंगलवार सुबह डिप्टी रेंजर राहुल यादव, वन दरोगा विनीत सक्सेना, अनूप, राममूर्ति, राजेंद्र की टीम ने दोबारा कॉम्बिंग की तो खेत की गीली मिट्टी में ताजा पगचिह्न दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि रविवार को भी गांव की उत्तर पश्चिम दिशा में बादल सरदार के झाला की तरफ तेंदुआ दिखा था।डिप्टी रेंजर राहुल यादव ने बताया कि यह गांव गोमती नदी के किनारे है। नदी किनारे घनी झाड़ियां हैं। अधिक गर्मी के कारण तेंदुआ अपनी प्यास बुझाने व छाया के लिए नदी के आसपास रहता है। उन्होंने बताया कि पगचिह्न तेंदुआ के ही हैं। ग्रामीणों को पंपलेट बांटकर सतर्क रहने को कहा गया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम को ताजा पगचिह्न मिले हैं। टीम ने तेंदुआ होने की पुष्टि करते हुए लोगों सतर्क रहने की सलाह दी है।प्रेमपुर निवासी उमाकांत ने बताया कि वह सोमवार देर शाम खेतों की ओर गए थे, तभी तेंदुआ दिखा।

उमस कर रही बेहाल, राहत की बूंदों का अभी करना होगा इंतजार

सीतापुर (संवाददाता)। जिले में लोगों को उमस भरी चिपचिपी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। बारिश का इंतजार लंबा होने से हर कोई व्याकुल है। बुधवार को सुबह से ही सूरज व बादलों के बीच लुका–छिपी का खेल शुरू हो गया। दोपहर बाद कुछ इलाकों में बौछारें पड़ीं। इसके बाद फिर तीखी धूप ने लोगों को पसीना–पसीना कर दिया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगे भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अच्छी बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है।मौसम के मिजाज में लगातार उतार–चढ़ाव के बाद भी बारिश नहीं हो रही है। बुधवार को सुबह से ही सूरज व बादलों के बीच लुका–छिपी का खेल शुरू हो गया। दोपहर बाद कुछ इलाकों में बौछारें पड़ीं। इसके बाद फिर तीखी धूप ने लोगों को पसीना–पसीना कर दिया।

पुलिस ने औपचारिक रूप से घटना का किया खुलासा

शादी का दबाव बनाने पर विवाहित प्रेमी ने अपने हाथ से घोंट था प्रेमिका का गला

सीतापुर (संवाददाता)। रामपुर मथुरा निवासी युवती की हत्या प्रेम प्रसंग में ही हुई थी। युवती विवाहित प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी। इससे परेशान प्रेमी ने गला दबाकर युवती की हत्या कर दी थी। इस बात की आशंका सोमवार को ही जाहिर कर दी गई थी।

एसपी ने मंगलवार को पुलिसलाइन में इसका औपचारिक रूप से खुलासा किया।बता दें कि एक गांव निवासी युवती का शव मक्के के खेत में पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने रामपुरमथुरा के लोधनपुरवा मजरा छतौनी निवासी अरमान को बांसुरा घाट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि वह मृतका के साथ एक मदरसे में पढ़ता था। इस दौरान युवती से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। बातचीत के लिए आरोपी ने एक छोटा मोबाइल खरीद कर युवती को दिया था। तीन महीने पहले युवक का विवाह दूसरी जगह हो गया।इसकी जानकारी जब युवती को हुई तो वह अरमान से शादी का दबाव बनाने लगी। इससे परेशान होकर अरमान ने गत 20 जून को युवती को मिलने के लिए मक्के के खेत में बुलाया और हाथ से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद युवती का फोन लेकर दुपट्टे को उसके गले में लपेट दिया और मोबाइल से अपना सिम निकाल कर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।एक साल पहले भाई–भाभी को हुई थी जानकारीकरीब एक साल पहले आरोपी से बात करते हुए युवती को उसकी भाभी ने पकड़ लिया था। भाभी ने भाई को भी यह बात बताई तो भाई ने युवक को डांटा भी था। इससे कुछ दिन तक तो बात बंद रही, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गई थी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि जिस फोन को बरामद किया गया था, उसमें आखिरी कॉल भी आरोपी के नंबर की ही थी। इससे पुलिस का शक गहराता चला गया। एसपी ने मंगलवार को पुलिसलाइन में इसका औपचारिक रूप से खुलासा किया।बता दें कि एक गांव निवासी युवती का शव मक्के के खेत में पाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने रामपुरमथुरा के लोधनपुरवा मजरा छतौनी निवासी अरमान को बांसुरा घाट के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि वह मृतका के साथ एक मदरसे में पढ़ता था। इस दौरान युवती से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। बातचीत के लिए आरोपी ने एक छोटा मोबाइल खरीद कर युवती को दिया था। तीन महीने पहले युवक का विवाह दूसरी जगह हो गया।इसकी जानकारी जब युवती को हुई तो वह अरमान से शादी का दबाव बनाने लगी।

अनुबंधित बस चालकों की मनमानी कायम

बाराबंकी (संवाददाता)। शहर में अनुबंधित बसों के चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। डीएम के सख्त निर्देश के बाद भी शहर के विभिन्न चौराहों, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अनुबंधित बसें खुलेआम सड़क किनारे खड़ी होकर सवारियों को बैठाती और उतारती दिखी। डीएम ने इसकी रोकथाम के लिए परिवहन विभाग व यातायात पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने का आदेश भी कागजी साबित हुआ। किसी भी जगह पर रोकथाम के लिए संयुक्त टीम की सक्रियता दिखाई नहीं दी। डीएम शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को हुई वाणिज्य बंधु समिति की बैठक में निर्देश दिया था कि अब कोई भी बस निर्धारित स्टॉप के अलावा कहीं नहीं रुकेगी।

दक्षता से मिलेगा बेहतर रोजगार

बाराबंकी (संवाददाता)। राजकीय औद्योगिक संस्थान महुआमऊ में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित तीन प्रमुख ट्रेडों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन ट्रेडों में 47 चयनित विद्यार्थी हाईटेक मशीनों की मदद से आधुनिक तकनीक की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने पर इन्हीं विद्यार्थियों को टाटा कंपनी में अप्रेंटिसशिप व प्लेसमेंट में भी वरीयता मिलेगी। टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से संस्थान को थ्रीडी प्रिंटिंग मशीन, सीएनसी मशीन, रोबोटिक आर्म्स, एडवांस टूलिंग मशीन, सॉफ्टवेयर आधारित ऑटोमेशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

ईसीसीई एजुकेटर की चयन प्रक्रिया की होगी जांच, जिलाधिकारी ने दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया

हरदोई (संवाददाता)। बाल वाटिका के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) एजुकेटर की चयन प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर डीएम की निगाह टेढ़ी हो गई है। जिलाधिकारी अनुनय झा ने पूरी प्रक्रिया की जांच कराए जाने का निर्णय लिया है।उन्होंने अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की है। समिति आवेदकों को फोन किए जाने से लेकर चयन कराने के आश्वासन तक की जांच करेगी। तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है।डीएम ने बताया कि कई माध्यम से उन्हें जानकारी व शिकायत मिली है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। ईसीसीई एजुकेटर पद के आवेदकों को वैसे तो अभिलेखों के सत्यापन के लिए फोन किए जाने के निर्देश थे, लेकिन आवेदकों को फोन कर अभिलेख सत्यापित कराने और चयनित कराए जाने के भी आश्वासन दिए गए हैं। चयन कराने के लिए आवेदकों को मुलाकात के लिए बुलाए जाने की भी जानकारी मिली है। इसके मद्देनजर एडीएम न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी और जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद को जांच समिति में नामित किया है।उल्लेखनीय है कि बाल वाटिका पर ईसीसीई एजुकेटर के 250 पदों के लिए 968 आवेदन विभाग को मिले थे। अभिलेखों के सत्यापन के लिए 750 आवेदकों को चयनित किया गया था। इसमें 450 आवेदकों ने अभिलेखों का सत्यापन कराया था। सत्यापन में 411 आवेदक पात्र मिले थे। 39 आवेदक पात्रता की श्रेणी में नहीं आ सके। ईसीसीई एजुकेटर पद पर चयन की प्रक्रिया पूरी कराते हुए सूची भी सार्वजनिक कर दी गई हैइसलिए भी उठे सवालविभाग से जुड़े विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि ईसीसीई एजुकेटर की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए शासन ने आउट सोर्सिंग कंपनी नामित की थी। शुरूआत में बेसिक शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने संबंधित कंपनी से सामंजस्य रखा, लेकिन अभ्यर्थियों के चयनित होने के बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी। सूची सार्वजनिक होने के बाद कंपनी को इसका पता चला। सूत्रों की मानें तो कंपनी की ओर से इस पर भी आपत्ति जताई गई।विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के एक करीबी कर्मचारी का नाम लेकर कई अभ्यर्थियों को फोन कॉल की गई थी। इस दौरान अभ्यर्थियों को चयनित कराने का भरोसा देकर विभाग में तैनात एक संविदा कर्मचारी से मुलाकात करने को भी कहा गया था। इसके पुख्ता प्रमाण भी प्रशासनिक अफसरों को मिले हैं। ईसीसीई एजुकेटर पद के आवेदकों को वैसे तो अभिलेखों के सत्यापन के लिए फोन किए जाने के निर्देश थे, लेकिन आवेदकों को फोन कर अभिलेख सत्यापित कराने और चयनित कराए जाने के भी आश्वासन दिए गए हैं। चयन कराने के लिए आवेदकों को मुलाकात के लिए बुलाए जाने की भी जानकारी मिली है।

शुरू होने से पहले ही बदहाल होती जा रही बावन की पब्लिक हेल्थ यूनिट

हरदोई (संवाददाता)। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बावन ब्लॉक में बनी पब्लिक हेल्थ यूनिट संचालित होने से पहले ही बदहाल होने लगी है। बीते एक साल से बनकर तैयार खड़ी पब्लिक हेल्थ यूनिट में अभी कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यूनिट में चढ़ने के लिए लगी रैंप की रेलिंग भी टूटने लगी है। वहीं, यूनिट के अंदर रखी लाखों की मशीनें भी धूल फांक रही हैं।15वें वित्त आयोग व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जांच और इलाज से संबंधित सुविधाएं बढ़ाने के लिए सभी सीएचसी पर बीपीएचयू यूनिट स्थापित की गई हैं। प्रत्येक भवन के निर्माण पर 48 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन समय बीतने के बाद अभी तक यूनिटें शुरू ही नहीं हुईं। बीते एक साल से बनकर तैयार खड़ी पब्लिक हेल्थ यूनिट में अभी कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यूनिट में चढ़ने के लिए लगी रैंप की रेलिंग भी टूटने लगी है।

काली नदी की पटरी और नीम नदी सफाई के लिए 54 लाख मंजूर

हरदोई (संवाददाता)। भूजलस्तर बढ़ाने के ब्लॉक स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों में तालाब खुदवाने के साथ ही अब ब्लॉक द्वारा नीम नदी की सफाई और काली नदी के पटरी सफाई का कार्य कराने के लिए बजट पास किया गया है।

मनरेगा योजना के तहत काली नदी की पटरी सफाई के लिए 32 लाख और नीम नदी की सफाई के लिए करीब 22 लाख रुपये का बजट पास हुआ है।काली नदी पर अतरौली के गांव रायपुर मुजफ्ता, आलमपुर, गदाईपुर, गांव खेड़ा, नरौना आकापुर, मीरगढ़ी, गोवली, चौंडौली बुजुर्ग, भावीगढ़, अहमदपुरा से होते हुए कौरह रघूपुरा तक पटरी सफाई का कार्य कराया जाएगा। वी–शेप में पटरी बनेगी और पटरी के सहारे बनी नालियों की सफाई होगी, जिससे उनमें होते हुए पानी काली नदी में जा सके। इस पर करीब 32 लाख रुपये खर्च होंगे और करीब 13 हजार मानव दिवस सृजित होंगे।

इसके साथ ही गांव चकाथल, बैजला, मलहपुर, मोहम्मपुर बढ़रा, कनकपुर, कुंजलपुर, धुर्रा प्रेमनगर, पनेहरा, महका, डडार अलूपुरा आदि स्थानों पर नीम नदी की सफाई–खुदाई का कार्य किया जाएगा। इसके लिए करीब 22 लाख रुपये का बजट मनरेगा से पास हुआ है। इसके निर्माण पर करीब नौ हजार मानव दिवस सृजित होंगे।

दीदी बन भरी स्वावलंबन की उड़ान

बाराबंकी (संवाददाता)। ब्लाक क्षेत्र के गढ़ी राखमऊ गांव की उपासना वर्मा ने ड्रोन दीदी बन स्वावलंबन की उड़ान भरी है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उपासना ड्रोन से फसलों में कीटनाशक, खाद व अन्य कृषि रसायन का छिड़काव कर अन्य महिलाओं को भी इस क्षेत्र में रोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

उपासना श्रीराम जानकी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष भी हैं। बेहतर काम करने के कारण इनका चयन ड्रोन दीदी के रूप में हुआ। पिछले वर्ष मार्च 2024 में ड्रोन मिला। एक जनवरी से 19 जनवरी तक हैदराबाद में ड्रोन का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

42 एकड़ में बनेगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, एक हजार करोड़ होंगे खर्च

गोरखपुर (संवाददाता)। गोरखपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास छह महीने के भीतर किया जा सकता है। डिजाइन को मंजूरी मिलने के बाद एस्टीमेट फाइनल होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद शिलान्यास का कार्यक्रम कर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। काम शुरू होने के बाद लगभग तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।

महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। 42 एकड़ में गोरखपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बनेगा। इसके लिए एयरफोर्स की ओर से लगभग 42.20 एकड़ जमीन एयरपोर्ट को दे दी है। इसको लेकर एयरपोर्ट पर मंगलवार को जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरफोर्स के बीएच एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए गए।

तीन माह में इसका डिजाइन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इसके निर्माण में एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।ए

माना जा रहा है कि अगले चार वर्षों में नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा।

एयरपोर्ट विस्तार के लिए एयरफोर्स मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) की जमीन दे रहा है। यह जमीन वर्तमान एयरपोर्ट से सटी है। यहां एयरफोर्स की कई बिल्डिंग भी है, जिसे एयरफोर्स कॉलोनी की ओर शिफ्ट किया जा रहा है।

मनबढ़ों ने बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष को पीटकर किया घायल

गोरखपुर (संवाददाता)। पुलिस को दी तहरीर में रामनयन आजाद ने बताया कि सोमवार शाम सात वह घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि तीन बाहरी लड़के किसी लड़की को लेकर नहर की ओर जा रहे हैं। मौके पर पहुंचने पर पता चला एक ई–रिक्शा में तीन युवक अपने कुछ साथियों का इंतजार कर रहे हैं। गगहा थाना क्षेत्र के भाटपार गांव निवासी व बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामनयन आजाद को तीन मनबढ़ युवकों ने सोमवार की देर शाम पीटकर घायल कर दिया।

मनबढ़ों के हमले में रामनयन का सिर फट गया और वह बेहोश होकर गिर पड़े। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ लिया व गगहा पुलिस को सौंप दिया।पुलिस को दी तहरीर में रामनयन आजाद ने बताया कि सोमवार शाम सात वह घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने बताया इसी दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि तीन बाहरी लड़के किसी लड़की को लेकर नहर की ओर जा रहे हैं।

राजस्व विभाग के अफसर और व्यापारियों के बीच हुई बैठक

भवन के अलावा जमीन का भी मिलेगा मुआवजा, सीएम योगी के निर्देश पर मंथन शुरू

गोरखपुर (संवाददाता)। मंगलवार को पांडेयहाता और आर्य नगर के लोगों को मकान व दुकान के मुआवजे पर चर्चा के लिए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, राजस्व विभाग के अफसर और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। विधायक ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि चौड़ीकरण से प्रभावित हर मकान व उसकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा।

विरासत गलियारा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जो मकान टूट रहे हैं और उनके मालिकों के पास जमीन का कागजात नहीं था, अब उन्हें भी कब्जे के आधार पर मुआवजा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व विभाग अब इसके लिए कानूनी उपाय खोज रहा है। इस पर चर्चा के लिए मंगलवार को अफसरों, भाजपा नेताओं, स्थानीय दुकानदारों और घर मालिकों के बीच बैठक भी हुई।पांडेय हाता से घंटाघर, आर्यनगर होते हुए धर्मशाला ओवरब्रिज के पास तक सड़क को विरासत गलियारा के रूप में विकसित किया जा रहा है। चौड़ीकरण की जद में आ रहे मकान और दुकानों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हो रही है। जब रजिस्ट्री कराकर मुआवजा देने का नंबर आया, तब पता लगा कि कई पीढ़ियों से बसे कुछ लोगों के पास जमीन का मालिकाना हक ही नहीं है।दरअसल, पहले यह जमीन जमींदार की थी, जिस पर व्यावहारिक रूप से लोग बस गए। बाद में पक्का मकान व दुकान बना लिया। न तो जमींदार ने अपनी जमीन खोजी और न ही घर बनाने वालों को चिंता हुई। जब मकान–दुकान टूटने लगे तब इन लोगों ने अपने जमीन का रिकॉर्ड खोजना शुरू किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई।

मकान का मुआवजा तो मिल रहा है, लेकिन जमीन उनके नाम नहीं होने की वजह से पेंच फंस गया। कुछ लोग कोर्ट गए तो वहां से नियमानुसार भुगतान का आदेश हो गया। इससे बात और उलझ गई। 21 जून की रात मुख्यमंत्री जब विरासत गलियारा का निरीक्षण करने गए तो वहां उन्होंने घोषणा की कि चौड़ीकरण से प्रभावित सभी लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके बाद प्रशासन ने फिर तैयारी शुरू की।

मंगलवार को पांडेयहाता और आर्य नगर के लोगों को मकान व दुकान के मुआवजे पर चर्चा के लिए गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, राजस्व विभाग के अफसर और व्यापारियों के बीच बैठक हुई। विधायक ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि चौड़ीकरण से प्रभावित हर मकान व उसकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा।नायब तहसीलदार प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि प्रभावित लोगों के जमीन के रिकार्ड खोजे जाएंगे। राजस्व नियमों के तहत कैसे इन लोगों को क्षतिपूर्ति दी जा सकती है, इसका उपाय खोजा जा रहा है। किसी भी प्रभावित को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

बैठक में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, व्यापारी नेता मदन अग्रहरि, प्रवीण मोदी, आशीष गुप्ता संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।

आधार के लिए कड़ी धूप में कतार

सीतापुर (संवाददाता)। मछरेहटा डाकघर में आधार बनवाने के लिए ग्रामीणों को जंग लड़नी पड़ रही है। आलम यह है कि घंटों धूप में पसीना बहाने के बाद भी संशोधन या नया आधार नहीं बन पा रहा है। कस्बे के पोस्ट ऑफिस में मंगलवार को सुबह से ही बच्चे अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुंच गए। लोगों ने आरोप लगाया कि आधार कार्ड बनाने वाले जिम्मेदार समय से डाकघर नहीं पहुंच रहे हैं।आधार में संशोधन कराने के लिए लोग कई दिनों तक भटकने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है। तपती गर्मी में घंटों बाद लोगों को आधार कार्ड बनवाने के लिए टोकन नसीब हो पा रहे हैं। मंगलवार को सुबह 10रू30 बजे कतार में खड़े मिले राहुल ने बताया कि 10 बजे से पहले ही डाकघर आ गए थे। यहां अभी तक आधार बनाने वाली मैडम नहीं आई हैं। सुबह करीब 10रू40 बजे डाकघर में लोगों की भीड़ बढ़ गई। इससे धक्का–मुक्की शुरू हो गई। डाकघर के गेट तक पहुंचने के लिए लोगो को खासी मशक्कत करनी पड़ी।

देश में आपातकाल लागू होने की ५०वीं बरसी पर डी0पी0आर0सी0 सेंटर में प्रदर्शनी का हुआ आयोजन

मा0 जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने फीता काटकर किया शुभारम्भ

श्रावस्ती, 25 जून, 2025। सू0वि0। देश में आपातकाल लागू होने की 50वीं बरसी पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशानुसार जनपद के विकास भवन स्थित डी0पी0आर0सी0 सेंटर में विशेष प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका मा0 विधायक रामफेरन पाण्डेय, मा0 जिलाध्यक्ष डा0 मिश्रीलाल वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद एवं अपर जिलाधिकारी (वि0ध्रा0) अमरेन्द्र कुमार वर्मा फीता काटकर शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में आपातकाल दिवस विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका माननीय विधायक, श्रावस्ती,जिलाध्यक्ष भाजपा एवं मुख्य विकास अधिकारी ने अवलोकन भी किया। इस दौरान 05 लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। आयोजित प्रदर्शनी में आपातकाल कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जन आंदोलनों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया।

इस अवसर पर मा0 विधायक ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए आपातकाल को इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। जिसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया गया था। इतिहास में सदैव इसे काले अक्षरों में लिखा जाएगा।

मा0 जिलाध्यक्ष ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता का पुनः स्मरण कराता है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदैव सजग रहें।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी पीयूष जायसवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी नन्दलाल, जिला समन्वयक डा0 राज कुमार त्रिपाठी, हरिगेन्द्र वर्मा सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण, विद्यालय के छात्र–छात्राएं एवं आम जनमानस उपस्थित रहे।

जायसवाल क्लब का हैदराबाद में 8वा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक :- प्रकाश जायसवाल।।

वाराणसी राजेश सेठ

जायसवाल क्लब प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी ने जानकारी दी कि विगत हर वर्ष की भांति जायसवाल क्लब की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हैदराबाद में होना सुनिश्चित किया गया है। जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक मनोज जायसवाल जी के निर्देश पर हैदराबाद में होने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के कई प्रांत से स्वजातीय समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद बैठक राकेश जायसवाल राष्ट्रीय महासचिव (हैदराबाद) व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंदलाल जायसवाल के नेतृत्व में होने जा रही हैं।

क्लब के प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल जी ने बतलाया कि हैदराबाद में होने वालें 2 दिवसीय 8वां राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महासम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्षध्संस्थापक मनोज जायसवाल जी उपस्थित होकर जिस तरह देश के कोने कोने में समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आए हुए समाज के लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा और गति देने का कार्य करेंगे।।

श्रपः एस डी एम उतरौला के स्थानांतरण होने के बाद अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने शासन से एस डी एम तैनाती करने की मांग की है।

उतरौला बलरामपुर तहसील के उपजिला धिकारी उतरौला राजेन्द्र बहादुर का स्थानांतरण उपजिलाधिकारी इटावा होने के बाद शासन ने किसी उपजिलाधिकारी उतरौला के पद पर अभी तक किसी की तैनाती नहीं की गई है। उपजिलाधिकारी उतरौ ला के पद रिक्त होने के कारण से न्यायालय पर वाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वहीं पर आगामी त्योहार मोहर्रम के अगले माह में होने से उतरौला में शांति व्यव स्था व प्रशासनिक व्यव स्था पर सवालिया निशान उठने लगा है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अखिलेश सिंह नेशासन को भेजे गए पत्र में उप जिलाधिकारी उतरौला के पद पर तत्काल तैनाती करने की मांग की है।उतरौला तहसील के उपजिलाधिकारी राजेन्द्र बहादुर का स्थानांतरण उपजिला धिकारी इटावा में होने के बाद शासन ने किसी भी उपजिलाधिकारी उतरौला के पद पर तैनाती नहीं की है।उप जिलाधिकारी उतरौला के पद रिक्त होने के कारण से उनके न्याया लय पर वाद का निस्ता रण नहीं हो पा रहा है वहीं आगामी त्योहार मोहर्रम अगले माह में होने से उतरौला मेंशांति व्यवस्था व प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है।अधि वक्ता संघ उतरौला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने शासन को भेजे पत्र में उपजिलाधिकारी उतरौला के पद पर तत्काल तैनाती कराने की मांग की है।

लोक तंत्र सैनानियों को अंग चित्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया।

उतरौला बलरामपुर आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित एककार्यक्रम में आपातकाल केदौरान कांग्रेस सरकार के द्वारा विरोध में संविधान की रक्षा करने वाले लोक तंत्र रक्षक सेनानियों व वरिष्ठ जन को कैबिनेटध्प्रभारी मंत्री राकेश सचान के द्वारा सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को अंगवस्त्र व भगवान राम चन्द्र जी चित्र भेंटकर उन्हें सम्मानित किया गया। लोक तंत्र सेनानी अयोध्या प्रसाद, राधे श्याम,ओम प्रकाश त्रिपाठी,शिव प्रसाद व चौधरी इरशाद अहमद गद्दी आदि के साथ साथ वरिष्ठ जन बरसातीशर्मा जुग्गी लाल, रामानन्द जग राम, मनी राम,प्यारे लाल, दलजीत सिंह, किशोरी लाल, मोदन वाल,सालिक राम जाय सवाल,नवल किशोर गुप्त,मंगल प्रसाद आदि लोगों को भी सम्मानित किया गया।

बारिश से कई पॉश इलाकों में भरा पानी, चोक नालों की वजह से कुछ मोहल्लो के घरों में भी भरा बरसाती जल

लखनऊ (संवाददाता)। ` अलग–अलग इलाकों में रुक–रुक हुई बारिश से गोमतीनगर जैसी पॉश कॉलोनी सहित कई इलाकों में सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी तो हुई ही, घरों में फर्नीचर व अन्य सामान खराब भी हुआ। दोपहर बाद हुई करीब एक घंटे की ही बारिश में अयोध्यादास वार्ड में बड़े दुर्गा मंदिर के पास नाला चोक हो गया, जिससे मंदिर व आसपास के घरों में गंदा पानी भर गया। सड़क पर जलभराव से स्कूली बच्चों को भी परेशानी हुई। निरालानगर, अलीगंज, कपूरथला चौराहे के पास भी जलभराव हुआ। जानकीपुरम में सहारा एस्टेट जाने वाली रोड का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। कुछ दिन पहले यहां छोटा गड्ढा हुआ था, लेकिन उसकी मरम्मत में नहीं की गई। ऐसे में मंगलवार को हुई बारिश में सड़क का काफी हिस्सा बैठ गया। हादसा न हो, उसके लिए स्थानीय लोगों ने वहां पेड़ की डाल रख दी। खराब पड़े ये बाढ़ पंपिंग स्टेशन सरकटा नाला बाढ़ पंपिंग स्टेशन बुद्धा पार्क बाढ़ पंपिंग स्टेशन हाथी पार्क बाढ़ पंपिंग स्टेशन वजीरगंज बाढ़ पंपिंग स्टेशन घसियारी मंडी पंपिंग स्टेशन पक्का पुल बाढ़ पंपिंग स्टेशन बादशाह नगर पंपिंग स्टेशन गोमती नगर बाढ़ पंपिंग स्टेशन। दोपहर बाद हुई करीब एक घंटे की ही बारिश में अयोध्यादास वार्ड में बड़े दुर्गा मंदिर के पास नाला चोक हो गया, जिससे मंदिर व आसपास के घरों में गंदा पानी भर गया।

उत्तर रेलवे का मेगा ब्लॉक, कई गाड़ियां रद्द

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर रेलवे के कानपुर पुल वाया किनारा व मगरवारा स्टेशनों के बीच सोनिक स्टेशन यार्ड में पुल पर गर्डर रखे जाने से ब्लॉक लिया गया है। इसकी वजह से 25 जून को चलने वाली 12179 लखनऊ जंक्शन –आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर कानपुर सेंट्रल से चलाई जाएगी।

वापसी में 25 जून को 12180 आगरा फोर्ट–लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी कानपुर सेंट्रल में तक ही आएगी। बुधवार को चलने वाली 12004 नई दिल्ली–लखनऊ जं. शताब्दी एक्सप्रेस बदले हुए रूट गाजियाबाद–मुरादाबाद–लखनऊ जं. के रास्ते चलेगी।

सहकारिता विभाग का खेल, धरे रह गए 27 करोड़ के माइक्रो एटीएम

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए खरीदे गए करीब 27.96 करोड़ के माइक्रो एटीएम अफसरों की लापरवाही से धरे रह गए। कुछ समितियों में इनका संचालन शुरू जरूर हुआ, लेकिन कई स्थानों पर ये रखे–रखे खराब हो गए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से समितियों को समृद्ध करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की योजना तैयार की गई थी। इसके तहत पैक्स में माइक्रो एटीएम लगाने का फैसला हुआ था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत अक्तूबर 2020 में 7479 पैक्स के लिए 27.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था। कृषि विभाग ने इस धनराशि को सहकारिता विभाग को सौंप दिया। सहकारिता विभाग में उप्र. को–ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक ने मार्च 2021 में माइक्रो एटीएम खरीदा।

आपातकाल के 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार ने अपनी सत्ता इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा को बरकरार रखने के लिए लोकतन्त्र का गला घोंट दिया गया है, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान।

उतरौला बलरामपुर कांग्रेस की सरकार ने अपनी सता व इंदिरा इज इंडिया,इंडिया इज इंदिरा का नारा बरकरार रखने के लिए लोकतंत्र का गलाघोट करआपात काल लागू करके जनता सहित विपक्षी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया था। हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। यह बात कैबि नेट व प्रभारी मंत्रीराकेश सचान ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उतरौला के मनकापुर रोड ग्राम लालगंज में स्थित रायल मैरेज हाल के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रेस वार्ता के दौरान कही।उन्होंने यह भी कहा कि लोक सभा चुनाव में संविधान बचाओ का नारा लेकर निकलने वाले कांग्रेस ने उसी संविधान का गला घोंटने का काम किया हैकांग्रेस की राजनीति केवलकुछ लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रदेश व केन्द्र सरकार बिना कि सी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।2047 में भारत विकसित राष्ट्र होगा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने वाले अधि कारी के विरुद्ध कार्य वाही की जाएगी।अवैध ा संचालित मदरसों के सवाल पर उन्होंने बता या कि जांच कराकर कार्यवाही की जाने की बात कही है।भाजपा लोकतंत्र की रक्षा,संवि ध ान के अनुरूप सभी का साथ सभी का विका स के साथ साथ हीकार्य कर रही है। कानून व्यव स्था को लेकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रदेश व देश बराबर निरन्तर प्रगति पर चल रहा है। बाढ़ की समस्या पर प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस सम स्या पर स्वयं मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। बाढ़ से बचाव के ठोस कार्य धरातल पर किए जा रहे है। जनपद बलरामपुर का जितना विकास 8 वर्षों में हुआ है। उतना किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र,सदर विधायक पल्टू राम,विधायक राम प्रताप वर्मा, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, जिला पंचा यत अध्यक्ष आरती तिवारी, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि महिपाल चौधारी, ब्लाक प्रमुख राकेश तिवारी, शशांक कुमार वर्मा, विकास कुमार गुप्ता,के के गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अनूप चन्द गुप्ता,प्रधान अमर नाथ वर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, फणीन्द्र गुप्ता, अंकुर गुप्ता,अभिषेक गुप्ता, दुर्गा प्रसाद,अपूर्व सिंह, वरुण सिंह, बल रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी डी पी सिंह,सुधीर कुमार श्रीवास्तव,भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार वर्मा, हर वंश सिंह,हर्षित जाय सवाल, प्रमोद कुमार , राहुल राज,सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इसी दौरान कैबिनेटमंत्री ने आपातकाल की एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, प्रशासन के तरफ से मंत्री जी को गाड आफ ऑनर दिया गया।

कीटनाशी विक्रेता कृषकों को दें पक्की रशीद-जिला कृषि रक्षा अधिकारी

श्रावस्ती, 25 जून, 2025। सू0वि0। जिला कृषि रक्षा अधिकारी अनिल प्रसाद मिश्र ने बताया है कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराने हेतु एंव कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 (यथा संशोधित) के प्रविधानों को कडाई से लागू करने हेतु समय–समय पर निर्देश दिये जाते है। विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने पर कार्यवाही की जा सकती है। इस संदर्भ में अनिल प्रसाद मिश्रा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मैमोध्क्रेडिट, मैमोध्पक्की रसीद उपलब्ध करायी जाये, कीटनाशी रसायन का नाम बैच नम्बर, विनिमार्ण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित होना अनिवार्य है। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कीटनाशी लाईसेन्स से सम्बन्धित अभिलेखों यथा वितरण पंजिका, भण्डार पंजिका, रेट बोर्ड, इत्यादि को अद्यतन रखने का प्राविधान है। कीटनाशी लाईसेन्स की प्रति चस्पा एंव ग्रो सेफ फूड का पोस्टर प्रदर्शित किया जाये। कीटनाशी विक्रेता उसी कीटनाशी कम्पनीयों से क्रय– विक्रय का व्यापार करेगे जिनका कीटनाशी अधिकार पत्र का अंकन उनके कीटनाशी लाईसेन्स पर होगा।

कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकान पर अनिवार्य रूप से अपनी दुकान का नाम, कीटनाशी लाईसेन्स संख्या, प्रोपराईटर का नाम व मोबाईल नम्बर एंव प्रिय किसान बन्धु, कीटनाशी रसायन क्रय करते समय अपनी पक्की रसीदध्कैश मैमो अवश्य प्राप्त करें, का अंकन करना सुनिश्चित करें। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा बगैर कोई सूचना के अपनी दुकान बन्द नहीं करेगे। कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा बिना शैक्षिक योग्यता अथवा व्यापार तकनीकी सहायक के बगैर व्यापार नहीं करेगे। कीटनाशी विक्रेता प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से कीटनाशी रसायन क्रय विक्रय की सूचना कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि अधोहस्ताक्षरी एंव उच्चाधिकारियों द्वारा आपके प्रतिष्ठान निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों का पालन करते नही पाया जाता है तो सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेताओं के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विक्रेता का होगा एंव उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

श्रावस्ती, 25 जून, 2025। सू0वि0। जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 अमरनाथ यति ने बताया है कि उ0प्र0 पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 में विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु मास्टर डाटा तैयार करने हेतु 01 जुलाई, 2025 से तथा दशमोत्तर कक्षाओं के लिए दिनांक 07 जुलाई, 2025 से छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित बेवसाइटध्पोर्टल खुल जाएगा। उक्त निर्धारित अवधि में सभी शिक्षण संस्थाएं अपना मास्टर डाटा बेस अपडेट कर लें। कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 में अध्ययनरत सभी वर्गो के छात्रध्छात्राओं द्वारा 02 जुलाई, 2025 से 30 अक्टूबर, 2025 तक एवं उच्च कक्षाओंध्दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के छात्रध्छात्राओं द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक 04 चरणों में एवं सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं द्वारा 10 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक 02 चरणों में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए बेवसाइट खुली रहेगी।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रावस्तीध्नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा अधिकारी एवं सभी प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में प्रवेश के समय ही छात्रध्छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना अवगत कराते हुए उनके अभिभावको के आय प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र बनवाने एवं छात्रध्छात्राओं के आधार छच्ब् मैप्ड बैंक खाता खुलवाते हुए उन्हें समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

30 जून को बुलडोजर अभियान के खिलाफ होगा प्रदर्शन

लखनऊ (संवाददाता)। भाकपा माले राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा कि प्रदेश के अकेले बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर में ही 500 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए और 60 के करीब मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कानून का खुला उल्लंघन किया गया। वो मंगलवार को प्रदेश तराई अंचल के जिलों में मुसलमानों के पूजा स्थल और मदरसों पर चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान और सील करने की कार्यवाही की जांच कर लौटने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

पीड़ित प्रार्थी ने थाना प्रभारी से लगाई न्याय की गुहार।

उतरौला बलरामपुर अपने पैतृक भूमि पर लगाए गए अशोक एवं कटहल आदि के पौधों को जबरन उखाड़कर उखाड़ कर फेंक दिया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना रेहरा बाजार के प्रभारी से कार्यवाही करने की मांग की है। थाना रेहरा बाजार अन्तर्गत ग्राम पंचायत गजपुर ग्रिन्ट ग्राम बरगदवा के निवा सी मुश्ताक अहमद ने थाना रेहरा बाजार में एक लिखित तहरीर देकर कहा है, कि गांव की पैतृक भूमि पर वृक्ष लगा रहे थे। विपक्षीगण एहसान, रशीद, शब्बू पुत्र गण अब्दुल रशीद के द्वारा हमेशा पीड़ित की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप व कब्जा करने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। इससे पूर्व में विपक्षी की हरकतो से तंग हो चुका है। जिसके सम्बन्ध में पीड़ित प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को भी एक शिकायती पत्र दिया था। और यह आरोप लगाया था, कि विपक्षी काफी दबंग एवं सरकश किस्म केप्रवृत्ति व्यक्ति है। बुधवार की रात लगभग तीन बजे विपक्षी गण एहसान रशीद के द्वारा तिलखी बढ़या के निवासी अली अहमद के साथ चार पांच और उनके साथ अन्य लोग चौपहिया वाहन से आएं और लगाए गए वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दिया। आहट मिलने पर पीड़ित प्रार्थी ने जाग गया, उस पर अली अहमद ने जान से मारने व गाड़ी में बांधकर घसी ट ले जाने की धमकीदेने लगा। विपक्षियों की सर कशी एवं दबंगई से पीड़ित प्रार्थी के परिवार काफी भयभीत है।

सरकार ने बदला नियम, सामूहिक विवाह योजना में वर-वधू की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना की निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। कन्या के आधार सत्यापन में लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही विवाह स्थल पर वर–वधू दोनों की बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। विवाह में दी जाने वाली उपहार सामग्री, जलपान और भोजन आदि के मानक तैयार कर उनका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। एक ही स्थान पर 100 या उससे अधिक जोड़ों की शादियों की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ पात्र परिवार आसानी से ले सकें। इसके लिए कई स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। योजना में लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपहारों की गुणवत्ता और आपूर्ति में पारदर्शिता के लिए अब फर्मों के चयन की प्रक्रिया निदेशालय स्तर से की जाएगी, ताकि जिला स्तर पर किसी तरह की अनियमितता न हो।

अखिलेश यादव ने किया खुलासा, इसलिए तीन बागी विधायकों को किया निष्कासित

लखनऊ (संवाददाता)। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय समेत तीन विधायकों को इसलिए निष्कासित किया, ताकि उनके मंत्री बनने में आ रही तकनीकी दिक्कत को दूर किया जा सके।

उन्होंने कटाक्ष किया कि वोट लेने के एवज में जब सरकार इन्हें मंत्री बना देगी, तब शेष बागी विधायकों के मंत्री बनने के रास्ते में आ रही बाधा को इसी तरह दूर कर देंगे। अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से कहा जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाने में दिक्कत है। वे सपा के विधानसभा सदस्य हैं।

मंत्री बनेंगे तो उन्हें सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। जहां तक जानकारी है कि इन सभी विधायकों को मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया था। जिसके नाम में पैकेज (सेठ) हो, वो कितना बड़ा पैकेज दे सकता है, हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि निष्कासित विधायकों को मंत्री बनाए। हमने तकनीकी दिक्कत को दूर कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि अगली खेप में हम इसी तरह से कुछ और विधायक उन्हें मंत्री बनाने के लिए दे देंगे। यहां बता दें कि पार्टी ने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 में से 3 विधायकों मनोज पांडेय, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह पर करीब सवा साल बाद सोमवार को निष्कासन की कार्रवाई की है। वहीं, राकेश पांडेय, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य के बारे में कहा कि इनके निष्कासन की समय–सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है।

सपा सूत्रों का कहना है कि जिन बागी विधायकों को सपा ने निष्कासित नहीं किया है, उनके प्रकरण को सजातीय समाज के सामने रखकर सामाजिक समीकरण साधेगी। सपा संदेश देगी कि आड़े वक्त में इन विधायकों ने पार्टी को धोखा दिया, पर सपा नेतृत्व ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वहीं, पश्चाताप करने पर इनमें से कुछेक को दुबारा मौका भी दे सकती है।

पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक मनोज पांडेय अगर सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो उपचुनाव होने की स्थिति में सपा भी पूरी तैयारी से अपना प्रत्याशी उतारेगी। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि हम घोसी को दोहराएंगे। घोसी में भी 2022 में सपा के टिकट पर जीते दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था। जब वे उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर उतरे तो यह सीट फिर सपा ने जीत ली। उन्होंने कटाक्ष किया कि वोट लेने के एवज में जब सरकार इन्हें मंत्री बना देगी, तब शेष बागी विधायकों के मंत्री बनने के रास्ते में आ रही बाधा को इसी तरह दूर कर देंगे।

युवाओं की टोली बनेगी पुलिस की हमजोली

सीतापुर (संवादाता)। जिले के कुल 2353 राजस्व गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम समिति से चार युवाओं को जोड़ा जाएगा। ये युवा अपराध पर लगाम लगाने में स्थानीय पुलिस की मदद करेंगे। प्रथम चरण में 9412 युवाओं की टोली पुलिस की हमजोली बनेगी। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसमें जनसामान्य का सहयोग प्राप्त कर सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में पूर्व से गठित ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन करते हुए चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा समिति के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक 18 से 40 वर्ष तक के युवाओं का चयन किया जाएगा। उनके चरित्र का सत्यापन किया जाएगा,।

गोली लगने से घायल पूर्व प्रधान तोड़ा दम

सीतापुर (संवादाता)। इलाके के बरगदिया गांव के पूर्व प्रधान गोपीनाथ यादव (50) की लखनऊ में इलाज के दौरान सोमवार रात मौत हो गई। प्रधानी की रंजिश में उनको गत मार्च में घर जाते समय गोलियां मारी गई थीं। वह मौजूदा समय में एक अधिवक्ता के मुंशी भी थे। गत 10 मार्च की शाम वह कचहरी से घर लौट रहे थे, तभी रेलवे क्रासिंग के आगे जैतीखेड़ा गांव के प्रधान प्रतिनिधि सिमरन सिंह एवं उसके साथियों ने गोपीनाथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। उन्हें तीन गोलियां लगी थीं। हमलावर उनको मृत समझकर भाग निकले थे। मामले में पुलिस ने सात लोगों पर केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उधर, घायल गोपीनाथ को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया था।

तालाब से निकला विशालकाय मगरमच्छ

सीतापुर (संवादाता)। कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भदफर में सोमवार देर शाम तालाब के पास विशालकाय मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छ पंकज मिश्रा के घर के निकट स्थित तालाब के पास दिखा। सूचना पर ग्रामीण मौके पर जुट गए। इस दौरान गांव के योगेश अवस्थी ने मगरमच्छ का वीडियो बना लिया। उन्होंने बताया कि रोशनी देख कर मगरमच्छ वापस तालाब में चला गया। सूचना पर रात में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम के मुताबिक, मगरमच्छ का पता नहीं चल सका है। वन दरोगा अरविंद गिरि ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्होंने दोबारा टीम के साथ तालाब का निरीक्षण किया,।

छत से नीचे गिरा युवक मौत

हरदोई (संवाददाता)। बेहंदर कला गांव में छत पर सो रहा युवक करवट लेने के दौरान सोमवार रात नीचे जा गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राइवेट अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। कासिमपुर थाना क्षेत्र के बेहंदर कला गांव निवासी गोविंद कुमार (42) खेती करते थे। गर्मी ज्यादा होने के कारण वह परिवार समेत अपने मकान की छत पर सोते थे। सोमवार रात भी छत पर सोए थे। सोते समय करवट लेने के कारण वह छत से नीचे गिर गए। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। परिजन संडीला के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। परिजन शव गांव वापस ले आए। मृतक के भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरा। परिवार में पत्नी रिंकी, दो पुत्र व दो पुत्रियां हैं।

उपभोक्ता की दुनिया
साध्य हिन्दी दैनिक
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शारदा प्रसाद पाठक द्वारा शंकर प्रिंटिंग प्रेस निकट भरत मिलाप चौराहा, नई बाजार भिनगा से मुद्रित तथा ग्राम हन्नामार पोस्ट गिलौला जनपद श्रावस्ती उ0प्र0 से प्रकाशित।
सम्पादक
भगवान दीन पाठक
मो0– 91 94504 54367,
91 96530 13722
सभी विवादो का न्याय क्षेत्र श्रावस्ती होगा।